भ्रष्ट यूपीए-भ्रष्ट एनडीए-भ्रष्ट मुलायम और लैफ्ट

क्या होगा 2014 में ?

संसद के शीतकालीन सत्र में ममता बनर्जी ने मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, पर यह प्रस्ताव पहले के प्रस्ताावों की तरह औंधे मुंह गिर गया। इसके पहले ममता ने भाजपा के अलावा वामपंथी दलों से प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा था, उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लेफ्ट इस प्रस्ताव को रखता है तो तृणमूल कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। पर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ बीजू जनता दल सामने आया।

मुलायम की समाजवादी पार्टी और मायावती की बसपा केंद्र सरकार के समर्थन में है। तृणमूल के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करके लेफ्ट ने भी दिखा दिया है कि वह भ्रष्ट, नाकाबिल और देश को बेचने पर आमादा सोनिया मनमोहन सरकार के साथ है। मनमोहन कठपुतले हैं जिनकी डोर कठपुतली सोनिया के हाथों में हैं और सोनिया को अपने इशारों पर नचा रहे हैं साम्राज्यवादी आकाओं की मंडली।

ममता बनर्जी ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई के विरोध में यूपीए का साथ छोड़ा था। भाजपा समेत लेफ्ट और अन्य पार्टियों ने इसके खिलाफ भारत बंद किया था, सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया था, हंगामा बरपाया था; पर जब सरकार के खिलाफ़ संसद में एक्शन का वक्त आया तो इन्होंने चुप्पी साध लेना ही मुनासिब समझा। एक रहस्मय, खतरनाक, दुरभि-संधियों से भरी चुप्पी-देश की 80 फ़ीसदी ग़रीब जनता के खिलाफ़ साज़िश।

इस मुद्दे पर टीवी चैनलों पर चलने वाली 'महाबहसों' में भाजपा ने शर्मनाक तरीके से अपना बचाव किया। पार्टी इस सवाल पर धारा-184 के तहत बहस कराना चाहती थी, जिसमें मत-विभाजन होता है, पर सरकार के खिलाफ़ बहुमत होने के बावजूद वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हो सकती। भाजपा नेताओं का कहना था कि अगर यह बहस होती तो मत-विभाजन होने पर सभी पार्टियां 'एक्सपोज' हो जातीं, पर भूलना नहीं होगा कि जब एनडीए सत्ता में था, तब गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 100 फ़ीसदी एफडी आई का समर्थन किया था। यह प्रमाणित है दस्तावेजों से। फ़िर यह दोमुंहापन क्यों? क्या सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए? उसे उल्लू बनाने के लिए? क्या राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्ट नेता यह सोचते हैं कि जनता की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है?

बहरहाल, मल्टी ब्रांड रिटेल में 100 फ़ीसदी एफडी आई का मामला हो या देश के प्राकृतिक संसाधनों की साम्राज्यवादी लूट का, कांग्रेस हो लेफ्ट हो या राइट या क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप, किसी को कोई परवाह नहीं, जनता जाये भाड़ में, देश जाये जहन्नुम में, बस सत्ता कायम रहे।

पर जैसे हालात बनते जा रहे हैं, उनमें वर्तमान मनमोहन सरकार का कायम रहना कठिन तो होता ही जा रहा है, दूसरे विकल्प की भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।

भ्रष्टाचार में सिर से पांव तक डूबे भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि यूपीए सरकार वेंटिलेटर पर है, आंखे हैं देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, मुंह है बोल नहीं सकती, पैर है खड़ी नहीं हो सकती, हाथ है हिला नहीं

सकती, बस चलाचली की बेला है। यह कहते हुए गडकरी के चेहरे पर बड़ी शातिर मुस्कान थी। इसके बाद सुषमा स्वराज ने भी घोषणा की कि यह सरकार इसी शीतकालीन सत्र में चल बसेगी। पर कैसे? यह खुलासा करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी।

लेकिन सुषमा स्वराज, भाजपा के खेवनहार गडकरी और अरूण जेटली साहब को यह भूलाना नहीं चाहिए कि कुछ समय पहले ही भाजपा के शीर्ष पुरूष लालकृष्ण आडवाणी ने साफ-साफ कह दिया था कि 2014 में कांग्रेस का गठबंधन अगर सत्ता में वापस आने वाला नहीं तो भाजपा गठबंधन भी इस स्थिति में नहीं है कि वह सत्ता में आने का दावा कर सके। आडवाणी का यह आकलन निराधार नहीं है। यह आकलन यथार्थ के काफी करीब हैं। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, शीतकालीन सत्र में यह जाने वाली नहीं, यह तो अपना टर्म पूरा करके ही जाएगी, फिर दुबारा नहीं आने के लिए। 2014 में चुनावों के दौरान और चुनावो परांत भीषण राजनीतिक परिदृश्य बनने वाला है। अराजक शक्तियां मजबूत होंगी। 'कानून-व्यवस्था' को सड़कों पर आता देखा जायेगा।

यूपीए और एनडीए, दोनों प्रमुख गठबंधनों की कमजोर हालत को देखकर सपा सुप्रीमो राजनीति के शतरंज की बिसात पर गहरी चालें चलने में मशगूल हैं। उनका सपना है पीएम बनना और इसके लिए तीसरा मोर्चा और लेफ्ट। तब तक सोनिया के साथ हैं, साथ रहेंगे, पर वक्त आते ही पल्टी मारेंगे। मुलायम का पूरा राजनीतिक कॅरियर इस बात का गवाह है कि उन जैसा दूसरा कोई 'समाजवादी' इस हद तक अवसरवादी नहीं हुआ। भाजपा के हाथ से हथियार फिसल रहे हैं। घर में आग लगी हुई है। पार्टी में गडकरी को हटाने की मांग लगातार जोर पकड़ती चली जा रही है। आज एक, कल दूसरा और फिर तीसरा नेता गडकरी के खिलाफ़ आवाज बुलंद कर रहा है, पर संघ नेतृत्व और संघ की वजह से भाजपा नेतृत्व भी भ्रष्ट गडकरी के सयमर्थन में है। इसका ख़ामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा।

जद (यू)के साथ उसके रिश्ते आगे कैसे रहते हैं, यह देखने वाली बात है, क्योंकि अगर भाजपा कोई साम्प्रदायिक एजेंडा सामने रखती है तो नीतिश कुमार उसका साथ छोड़ने में देर नहीं करेंगे। मोदी के सवाल पर उन्होंने अपना रूख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यह अलग बात है कि जद (यू) अध्यक्ष शरद यादव का रूख ढुलमुल है, पर वे भी इस पोजिशन में नहीं हैं कि नीतिश को दर किनार कर सकें।

मनमोहन सिंह का चेहरा कोयले की 'कालिख' में सन चुका है। कांग्रेस से नेतृत्व उभर नहीं पा रहा है, राहुल का व्यक्तित्व करिश्माई साबित नहीं हो सका। सोनिया और उनके चमचे अगर अभी भी राहुल से किसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं तो भारी गफ़लत में हैं। कुल मिलाकर 2014 में एक बड़ा राजनीतिक शून्य उभर सकता है। संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है। अराजकता, अनिश्चितता और ऐसे में साम्राज्यवादी घुसपैठ और तेज होगी, विघटनवादी शक्तियां मजबूत होंगी। फ़िलहाल, राजनीतिक विकल्प एक स्वप्न-सा ही है।

- मनोज कुमार झा

मौसम की, महंगाई की या व्यवस्था की मार?

आम आदमी का जीना होगा और भी मुहाल

सरकार ने माना कि मानसून की बेरुखी से सूखा पड़ने की चिंता और महंगाई बढ़ रही है। पर यह सही कारणों से मुंह चुराने जैसा ही लगता है। जुलाई 2011 में भी देश में मानसून की स्थिति काफी चिंताजनक थी। पिछले साल जुलाई में सामान्य से करीब 16 फीसदी कम बारिश हुई थी। केवल 40 फीसदी बुआई के साथ स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इस बार 15 जुलाई तक देश में मानसून सामान्य से 22 फीसदी कम है। यानी अंतर सिर्फ 6 फीसदी का है। पर कीमतों में उछाल का अंतर काफी बड़ा है।

आलू पिछले साल जुलाई में 3-5 रुपये प्रति किलोग्राम था अभी इसकी कीमत 15-20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। एक साल पहले टमाटर के लिए सिर्फ 20-22 रुपये प्रति किलो चुकाने होते थे जो अब बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा हो गया था। यानी यहां भी करीब 2.5 गुना इजाफा। रसोई का सबसे अहम प्रोडक्ट कुकिंग ऑयल भी महंगाई से गर्म है। जुलाई 2011 में 65 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला सोयाबीन ऑयल इस साल जुलाई में 85 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर जा रहा है। चीनी भी 28-29 रुपये प्रति किलो ग्राम (पिछले जुलाई) से बढ़ कर 37-38 रुपये पर आ गई है।

सवाल है मानसून की स्थिति में केवल 6 फीसदी (2011 में 16 फीसदी कम और 2012 में 22 फीसदी) के अंतर से दाम में इतने बढ़ोत्तरी क्यों? इसके लिए कुल मिला कर सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। नौकरियों के अवसर में कमी, पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी, अनाजों के भंडारण की कमजोर व्यवस्था, रुपये की कमजोर होती स्थिति पर काबू पाने में नाकामी आदि से ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते महंगाई बढ़ी है।

महंगाई दर घटी, महंगाई नहीं

चालू वर्ष के जून महीने में जरुरी चीजों के दाम पिछले साल इसी महीने की तुलना में औसतन 10 फीसदी तक ज्यादा रहे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आलोच्य महीने में सब्जी, खाद्य तेल और दूध के दाम काफी ऊंचे रहे। इससे मुद्रास्फीति 10.02 फीसदी पर पहुंच गई है। दिलचस्प है कि मई में खुदरा बाजार में वार्षिक आधार पर महंगाई दर 10.36 फीसदी रही थी।

नौकरियों का अकाल

देश में नौकरियों को लेकर भी हालत खासी पतली है। कंपनियों ने नई भर्तियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मायहाइरिंगक्लब डॉट कॉम के सर्वे के मुताविक, चालू वित्त वर्ष में कंपनियों ने नई भर्तियां करना लगभग ठप कर दिया

है। वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में औसत जॉब एट्रीशन दर 17 फीसदी रही है। इसकी दो प्रमुख वजहें हैं। पहली वजह यह है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक वातावरण बेहद अस्थिर हैं। दूसरी तरफ, कंपनियों द्वारा भर्ती संबंधी गतिविधियों में भी कमी आई है।

तनख्वाह घटी, पर्चेजिंग पॉवर थमी

पिछले एक साल के आंकड़ों पर गौर करें तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों की सैलरी में अधिकतम 40 फीसदी तक कमी आई है। भारत की सभी बड़ी कंपनियों में चालू साल के लिए सैलरी कट हुई है। सैलरी में आई इस कमी से लोगों की पर्चेजिंग पॉवर भी काफी घट गई है। अब लोग बहुत जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च कर रहे हैं एचआर एक्सपर्ट्स की मानें तो आईटी और बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के बड़े अधिकारियों की सैलरी में इस साल और कमी हो सकती है। इनका कहना हैं कि रुपये की कमजोरी ज्यादा दिनो तक बाजार के खराब माहौल की भरपाई नहीं कर सकती है। दरअसल, आईटी कंपनियों को रुपये के टूटने से फायदा होता है।

मानसून, और नौकरियों का गणित

भारत की 60 फीसदी खेती मानसून पर निर्भर रहती है और जीडीपी ग्रोथ में खेती का योगदान 15 फीसदी से भी ज्यादा है। बारिश, अर्थव्यवस्था और नौकरियों का साथ तो चोली-दामन का होता है। यदि कमजोर मानसून रहा तो अच्छी बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी और यदि अच्छी फसल नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी और यदि महंगाई बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अर्थ व्यवस्था कमजोर होगी तो हमारी-आपकी नौकरी भी जा सकती है।

कमजोर रुपये से लगा महंगाई में तड़का

अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने और रुपये की कमजोरी से भी महंगाई पर असर पड़ा है। इसका सीधा असर निर्यातकों और निर्यात कर भारत में लाये जाने वाले उत्पाद पर पड़ता है। ऐसे में इन उत्पादों के लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने होते हैं।

मानसून की बेरुखी से निपटने के लिए सरकार की यह है योजना

सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव के अंतर्गत अंतर-मंत्री समूह गठित किया है। यह हर सप्ताह विभिन्न राज्यों और विभागों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समन्वय कर रहा है। खेती के लिए बिजली आपूर्ति की विशेष व्यवस्था की गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को अलग-अलग करीब 300 मेगावट बिजली दी जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उत्तर-पश्चिम भारत में डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। पेयजल, चारे और बुवाई के लिए बीज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित मंत्रालयों को दिये गये थे।

क्या हैं हालात :

देश भर में करीब 1080 लाख हेक्टेअर खरीफ रकबे में केवल 340 लाख हेक्टेअर में बुवाई 13 राज्यों के करीब 94 जिलों में सूखे से निपटने की कोशिशें तत्काल शुरू करने की जरूरत है। देश के एक बड़े हिस्से में 30 जून तक खरीफ की बुवाई शुरू नहीं हो सकी थी। देश के 210 जिलों में स्थिति साफ नहीं।

-मनोज कुमार झा